

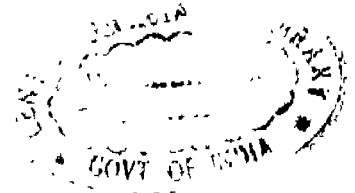


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 187 ]  
No. 187 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 1996/आश्विन 24, 1918  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1996/ASVINA 24, 1918

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1996

सं. 1/50/96-ईपी (टी एण्ड जे)-1.—विषय : उन देशों को परिधान तथा निटवियर निर्यात करने के लिए वर्ष 1996—98 की अवधि के दौरान लागू होने वाली शर्तें, जिनमें ऐसे निर्यात वस्त्र और कलादिंग संबंधी करार के उपबंधों के अन्तर्गत प्रतिबंधित है।

## 1. प्रस्तावना :

सिलेसिलाए परिधानों तथा निटवियर के संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के संबंध में निर्यात तथा आयात नीति (1992—1997) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया नियम पुस्तिका के खण्ड 1 के परिशिष्ट 43 के खण्ड-I की मद संख्या II में निहित उपबंधों के अनुसरण में तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 1/64/95-ईपी (टी एण्ड जे)-1 समय-समय पर तथा संशोधित का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 1997 से 1999 के लिए हकदारियों के आबंटन संबंधी नीति (जिसे इसके पश्चात आबंटन नीति कहा गया है) इसमें पश्चात स्पष्ट किए गए अनुसार होगी।

## 2. प्रशासन :

1. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, निर्यात हकदारियों का आबंटन करेगा। इस आबंटन नीति के अन्तर्गत आने वाले सिलेसिलाए परिधानों तथा निटवियर के सभी निर्यातों के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण भी महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद का अभिप्राय उनसे तथा ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा जिन्हें वो आवश्यक उत्तरदायित्व अंशतः अथवा पूर्णतः स्पष्टतया अथवा अन्यथा प्रत्यायोजित करें।
3. महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आबंटन नीति के क्रियान्वयन के लिए वे वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।
4. वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के निर्वचन संबंध में अंतिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन अधिकरणों, उनके कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुनर्आबंटित कर सकता है, जैसा कि उचित समझे।
5. निर्यात हकदारियों का आबंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को किया जाएगा जो निर्यात-आयात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

**3. आधार वर्ष :**

इस अधिसूचना में एक आबंटन वर्ष के लिए वाक्यांश "आधार वर्ष" जहां कहीं भी प्रयुक्त हो, उसका अभिप्राय उस कैलेंडर वर्ष से होगा जो आबंटन वर्ष के ठीक पहले वाले वर्ष से पहले होगा। उदाहरणार्थ वर्ष 1997 के लिए आधार वर्ष 1995 होगा।

**4. आबंटन की प्रणाली :**

1. प्रत्येक आबंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आबंटन निम्नलिखित प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक मद के सामने दिखाई गई दरों पर किया जाएगा :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पीपीई)	75
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	(5)
(ख) नए निवेशक हकदारी (एन आई इ)	10
(ग) पहले आओ पहले पाओ हकदारी (एफसीएफ एस)	10
(घ) गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन व्यू इ)	5
योग	100

2. समय-समय पर अभ्यर्णों, लोचशीलताओं या अन्यथा उपलब्ध होने वाली मात्राओं को भी पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन किया जाएगा।
3. मांग पैटर्न और अन्य सम्बद्ध कारकों में परिवर्तनों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियां आबंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित होगा।
4. वस्त्र आयुक्त भिटवियर, ऊनी उत्पादों, बाल परिधानों या किसी अन्य मद अनुसार मात्रा आरक्षित कर सकता है। ऐसे आरक्षण 30 सितम्बर तक लागू होंगे तथा 1 अक्टूबर की स्थिति अनुसार आरक्षित मात्राओं में से गैर-आबंटित अधिशेष पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में ऐसी मदों के लिए किन्हीं आरक्षणों के बिना आवेदनों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

**5. उच्च मूल्य हकदारी (एचवीई) सहित विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी पी ई) :****परिक्लन—सामान्य**

1. महाविदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद विगत हकदारी का परिक्लन निम्नलिखित आधार पर करेगा।
2. उपलब्ध मात्रा का समानुपात आबंटन आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक देश-श्रेणी में आबंटन वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि, आबंटन को उक्त अवधि के दौरान उक्त देश-श्रेणी में भारत के निर्यात निष्पादन तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

**3. परिक्लन—एच.वी.ई.**

जिन निर्यातकों ने आधार वर्ष के दौरान किसी देश-श्रेणी विशेष में विगत निर्यात हकदारी के लिए आवेदन किया है उन सभी निर्यातकों की औसत इकाई मूल्य वसूली का निर्धारण किया जाएगा तथा और ऐसे निर्यातक जिन्होंने औसत इकाई मूल्य से उच्च इकाई मूल्य वसूल किया है, उन्हें उस देश-श्रेणी को अलग-अलग निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात से गुणा करके एक देश-श्रेणी में वसूले गए इकाई मूल्य तथा निर्यातक द्वारा वसूले गए औसत इकाई मूल्य के अन्तर के आधार पर 5 प्रतिशत आरक्षित पूल (एचवीई) में से अतिरिक्त मात्राएं आबंटित की जाएंगी। अलग-अलग निर्यातकों की एचवीई को उनकी पी पी ई में जोड़ा जाएगा तथा यह पी पी ई पर लागू होने वाली सभी शर्तों के अध्याधीन होगा।

**उपयोग की अवधि**

4. आबंटनों का उपयोग किए जाने के प्रयोजन से 1 जनवरी से 30 सितम्बर तक की एकल अवधि होगी। निर्यातकों को 30 सितम्बर तक अपनी हकदारियों का उपयोग करना होगा।

**अवधि बढ़ाना**

5. 30 सितम्बर के बाद अप्रयुक्त मात्राओं को नीचे दी गई दर पर ई एम डी/बी जी के आधार पर उसी वर्ष को 31 दिसम्बर तक इस शर्त पर आगे बढ़ा दिया जाएगा कि अवधि बढ़ाने का अनुरोध किसी विशिष्ट क्रेता के लिए हो तथा क्रेता को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**उत्पाद गुप**

संयुक्त राज्य अमरीका में ग्लोबल

कनाडा में अंडर चीयर

कनाडा में गुप "ए"

**ई एम डी/बी जी राशि**

5 रु. प्रति जोड़ा

5 रु. प्रति नग

18 रु. प्रति वर्ग मीटर

संयुक्त राज्य अमरीका में ग्रुप-2	18 रु. प्रति एस एम ई
यूरोपीय यूनियन में श्रेणी 4, 5 और 24	18 रु. प्रति नग
अन्य	32 रु. प्रति नग

6. ऐसी समय वृद्धि के लिए हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र हकदारी की प्रारम्भिक वैधता की समाप्ति से पूर्व अथवा 3 दिन की छूट अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

#### आबंटन के लिए आवेदन

7. प्रणाली के उद्दिष्ट मात्राएं 1 जनवरी को उपलब्ध होंगी, तथा इस प्रयोजन के लिए पूर्व वर्ष में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं ।  
हस्तांतरण संबंधी शर्तें
8. पी पी ई 20 सितम्बर तक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से हस्तांतरणीय होगी । तथापि, 31 मई के बाद के हस्तांतरण उस वर्ष के लिए सम्बद्ध देश/श्रेणी में हस्तांतरणकर्ता को आबंटित की गई कुल मात्रा के 50 प्रतिशत तक ही सीमित होंगे ।
9. अन्तर्गत विगत निर्यात हकदारी 1 इसके पश्चात् जिसका उल्लेख पी पी टी के रूप में किया गया है उस वर्ष के 30 सितम्बर तक वैध रहेगी तथा उसे 31 दिसम्बर तक बढ़ाया जा सकता है जो कि उपर्युक्त पैरा 5(4) के उपबन्धों के अध्वधीन होगी ।
10. पी पी टी के आधार पर पोत लदानों की गणना हस्तांतरण द्वारा किए गए निर्यात के रूप में की जाएगी ।
11. पी पी टी के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी ।

#### हस्तांतरण प्रणाली

12. विगत निर्यात निष्पादन हकदारी महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आम लाइन कम्प्यूटर नेटवर्क की सहायता से इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण योजना के माध्यम से विनियमित किया जाएगा जिसमें से अभिप्रेत हस्तांतरण कर्ताओं के प्रस्ताव मात्रा तथा कौटा लाभांश सहित अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा तथा अभिप्रेत हस्तांतरी ऐसे प्रदर्शित प्रस्तावों के आधार पर हस्तांतरण के लिए अनुरोध करेंगे । ये अनुरोध पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रसंस्कृत किए जाएंगे जिसमें प्राप्त प्रथम अनुरोध तथा इसी प्रकार के अन्य के लिए न्यूनतम लाभांश राशि पर प्रस्ताव के आबंटन की परिकल्पना है ।
13. इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण योजना तथा इसे जिस तारीख को लागू किया जाएगा, की घोषणा महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पृथक् रूप से की जाएगी । इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण योजना के लागू होने तक विगत निर्यात निष्पादन हकदारी हस्तांतरण इस समय प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित किए जाएंगे । महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद घोषित इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण योजना में है, जब कभी वे आवश्यक समझें, व्यापार को पर्याप्त नोटिस देकर कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं ।

#### 6. पहले आओ पहले पाओ ( एफ सी एफ एस ) प्रणाली :

##### रिलीज अनुसूची

- (1) पहले आओ पहले पाओ के लिए उद्दिष्ट 10% मात्राएं 10 जनवरी तथा 10 अप्रैल को दो बराबर किस्तों में रिलीज की जाएंगी ।
- (2) अभ्यर्पणों, लोचशीलताओं अथवा अन्यथा, यदि कोई हो के द्वारा उपलब्ध मात्राएं 10 जुलाई तथा 10 नवंबर को रिलीज की जाएंगी । इसके अतिरिक्त 1 सितंबर की स्थिति अनुसार नव निदेशक हकदारी प्रणाली में गैर आबंटित अधिशेषों को 1 अक्टूबर से इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए पहले आओ पहले पाओ में बदल दिया जाएगा । देश-श्रेणियों तथा मदों जहां कि रिलीज की जाने वाली मात्राएं महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा नियत रिलीज से पूर्व पर्याप्त समय रहते घोषित की जाएंगी ।

##### आवेदन-पत्र

- (3) आवेदन की तारीख को वैध एल सी द्वारा समर्थित आवेदन पत्रों के प्रति मात्राएं आबंटित की जाएंगी ।

##### आबंटनों की वैधता

- (4) आबंटन किए जाने की तारीख से 75 दिनों तक आबंटन वैध रहेंगे तथा कोई समय वृद्धि नहीं दी जाएगी ।

##### आबंटन की प्रणाली

- (5) पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत आबंटन इसमें शामिल मात्रा के एफ ओ बी मूल्य के 5% की दर से ई एम डी/बी जी के अध्वधीन होगी ।
- (6) वस्त्र आयुक्त उस अधिकतम मात्रा का निर्धारण करेंगे जो कि किसी आवेदनकर्ता द्वारा इस प्रणाली के अंतर्गत प्रतिदिन प्रत्येक देश-श्रेणी के लिए लागू की जा सकती है ।
- (7) आबंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किए जाएंगे तथा किसी दिन जब उपलब्ध मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक हो, पात्रता का निर्धारण उस दिन प्राप्त आवेदन पत्रों में से उच्च इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा ।

##### हस्तांतरणीयता

- (8) पहले आओ पहले पाओ आबंटन हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

**7. नव निवेशक हकदारी (एन आई ई) :****आर्बंटन**

- (1) नव निवेशक हकदारी प्रणाली में आर्बंटन केवल उन निर्यातकों तक सीमित होगा जो विनिर्माता-निर्यातक के रूप में पंजीकृत हैं तथा जिन्होंने उस आधार वर्ष की पहली जनवरी को शुरू होने वाली बाद की 12 महीनों की क्रमिक अवधि के दौरान मौजूदा एकक अथवा नए एकक में नई मशीनों में न्यूनतम 50 लाख रुपये की राशि निवेश की हो। एन आई ई आर्बंटन निवेश के एक ब्लाक विशेष के लिए केवल एक बार ही किया जाएगा।
- (2) आर्बंटन.—आर्बंटन वर्ष के 31 अगस्त तक प्राप्त होने वाले आवेदनों तक ही सीमित होगा तथा 1 सितम्बर की स्थिति अनुसार नव निवेशक हकदारी प्रणाली में बचे हुए गैर-आर्बंटित अधिशेषों को पहले आठो पहले पाओ प्रणाली में बदल दिया जाएगा।
- (3) इस प्रणाली में स्वीकार्य निवेश की 1 लाख रुपये की प्रत्येक राशि के लिए 1000 नग की दर से मात्राएं आर्बंटित की जाएंगी। नव निवेशक हकदारी का आर्बंटन करने के लिए निवेश में एक लाख रुपये की विभाजित राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (4) एक विशिष्ट आवेदनकर्ता जिस मात्रा का पात्र है उसे आवेदनकर्ता द्वारा चुने गए कम से कम 5 देशों-श्रेणियों में बराबर विभाजित किया जाएगा। अर्थात् प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए स्वीकार्य आर्बंटन केवल विनिर्माता एकक की उत्पादन सुविधाओं से युक्त देश-श्रेणियों को ही किया जाएगा। निवेश की एक लाख रुपये की प्रत्येक राशि के लिए अधिकतम हकदारी 200 नग होगी। यदि कोई निर्यातक इसलिए 5 देशों/श्रेणियों से कम का चयन करने के लिए बाध्य है क्योंकि उसके उत्पाद की मर्दे 5 देश/श्रेणियों में उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में उसे आर्बंटित की गई कुल मात्रा उसकी रूप के देश-श्रेणियों तक ही सीमित होगी जिसे स्वीकार्य निवेश की एक लाख रुपये की प्रत्येक राशि के लिए 200 नगों द्वारा गुणा किया जाएगा। यदि कोई निर्यातक 5 से अधिक देशों-श्रेणियों का चुनाव करता है तो उस स्थिति में उसके नव निवेशक हकदारी आर्बंटन को विभिन्न देशों-श्रेणियों के बीच बराबर वितरित किया जाएगा जो कि स्वीकार्य निवेश की एक लाख रुपये की प्रत्येक राशि के लिए 1000 नग की अधिकतम के अन्वेषी होगी।

**आर्बंटनों का उपयोग**

- (5) निर्यातकों को 30 सितंबर तक अपनी हकदारियों का उपयोग करना चाहिए। 30 सितंबर के बाद अप्रयुक्त मात्राएं उसी वर्ष के 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती हैं जो कि विगत निर्यात निष्पादन हकदारियों की ऐसी समय वृद्धि के लिए लागू उन्हीं शर्तों के अन्वेषी होंगी।

**हस्तांतरणीयता**

- (6) नव निवेशक हकदारी हस्तांतरणीय नहीं होगी।

**वस्त्र आयुक्त द्वारा दिशा निर्देश**

- (7) वस्त्र आयुक्त द्वारा पात्रता तथा आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वस्त्र आयुक्त पत्र आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे तथा विशिष्ट निर्यातकों के निवेश के स्वीकार्य मूल्य का निर्णय करेंगे। उक्त आधार पर महा निदेशक, ए ई पी सी द्वारा हकदारियों का आर्बंटन किया जाएगा।

**विविध**

- (8) वर्ष 1996 के लिए नव निवेशक हकदारी आवेदनों के प्रति आर्बंटन/समय वृद्धि के लिए उद्दिष्ट मात्राएं वर्ष 1977 के लिए नव निवेशक हकदारी प्रणाली के लिए उद्दिष्ट 10% स्तरों में से बटा दी जाएगी तथा ऐसे आर्बंटनों/समय वृद्धि के पश्चात् बचने वाले अधिशेष को वर्ष 1997 के लिए प्राप्त आवेदनों के प्रति आर्बंटित किया जाएगा।
- (9) यदि किसी देश-श्रेणी में किसी नव निवेशक हकदारी का अधिशेष उपलब्ध नहीं है जहां कि एक निर्यातक आर्बंटन की इच्छा व्यक्त करता है, तो इसको या तो किसी अन्य देश-श्रेणी के लिए, जहां कि वह पात्र है, अधिशेष उपलब्ध है अथवा बाद के आर्बंटन वर्ष के लिए उसी देश-श्रेणी में आर्बंटन के लिए चयन करने का विकल्प होगा।

**8. गैर-कोटा निर्यातक हकदारी प्रणाली :**

- (1) गैर कोटा देशों को परिधानों तथा कोटा देशों को गैर-कोटा परिधानों के निर्यातक इस प्रणाली के अंतर्गत आर्बंटन के पात्र होंगे बशर्ते कि भुगतान मुक्त मुद्रा में प्राप्त हो, तथा आधार वर्ष के दौरान एक निर्यातक का न्यूनतम निर्यात निष्पादन 15 लाख रु. हो। तथापि रूस को परिधानों के निर्यातों पर गैर-कोटा निर्यातक हकदारी आर्बंटनों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**अभिकरण**

- (2) इस प्रणाली के अंतर्गत हकदारियों का परिकलन तथा आर्बंटन आधार वर्ष के दौरान स्वीकार्य निर्यातों के मूल्य के आधार पर महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा तथा उपलब्ध स्तरों को अलग-अलग आवेदनों के निर्यातों के मूल्यों के आधार पर समान अनुपात में वितरित किया जाएगा।
- (3) एक निर्यातक को आर्बंटन के लिए दस देश-श्रेणियों के संयोजन का विकल्प रखने की अनुमति दी जाएगी।
- (4) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी पर लागू शर्तें आवश्यक परिवर्तनों के साथ गैर-कोटा निर्यात हकदारी पर भी लागू होंगी।

**हस्तांतरणीयता**

- (5) गैर-कोटा निर्यात हकदारी हस्तांतरणीय है (जो कि हस्तांतरण के बाद गैर-कोटा हस्तांतरण के नाम से उल्लेखित होगी) तथा हस्तांतरण की शर्तें विगत निर्यात निष्पादन हकदारी के मामले में लागू शर्तों के समान होंगी।

**9. शिपिंग बिलों के प्रमाणन की वैधता :**

- (1) हस्तांतरित विगत निर्यात निष्पादन तथा हस्तांतरित गैर-कोटा तथा नव निवेशक हकदारी सहित विगत निर्यात निष्पादन हकदारी तथा गैर-कोटा हकदारी प्रणाली के संबंध में शिपिंग बिलों के प्रमाणन वैधता 75 दिन तक अथवा हकदारी प्रमाण-पत्र की वैधता तक होगी। इसमें से जो भी पहले हो। पुनर्वैधता की अनुमति हकदारी प्रमाण-पत्र की समाप्ति तक दी जाएगी।
- (2) पहले आओ पहले पाओ आबंटनों के संबंध में शिपिंग बिलों के प्रमाणन की वैधता, आबंटन की तारीख से 75 दिनों के लिए होगी। इसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (3) इस पैरा में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद वस्त्र आयुक्त अलग-अलग मामलों में पांच कार्य दिवसों तक वैधता अवधि को बढ़ा सकते हैं बशर्त कि वे इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि संबंधित निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर परिस्थितियां होने के कारण इस अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर सका था।

**10. कम कारोबार वाली मदें :**

- (1) किसी मद को कम कारोबार वाली मद के रूप में घोषित किया जाएगा यदि आधार-वर्ष के दौरान उसका उपयोग, आधार स्तर के 75 प्रतिशत से कम रहा हो। महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद पिछले वर्ष से अधिक से अधिक 1 दिसंबर तक उन मदों को घोषित करेंगे जो कम कारोबार वाली मदें हैं।
- (2) इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध में अन्यत्र निहित प्रावधान के बावजूद कम कारोबार वाली मदों को सामान्यतः निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी।
  - (क) निर्यातक को पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत 5% की बजाए एफ ओ बी मूल्य का प्रतिशत ई एम डी/ बी जी के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
  - (ख) उपर्युक्त पैरा 6(4) के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के लिए निर्धारित मात्रा संबंधी अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।
  - (ग) पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उपर्युक्त पैरा 6(3) में निर्धारित लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (घ) आनुपातिक जल्दी के लिए उपयोग की सीमा दूसरे देश-श्रेणियों में लागू 75% की बजाए आबंटित मात्राओं का 50% होगी।
- (3) वस्त्र आयुक्त द्वारा चालू मांग पैटर्न के आधार पर बिना कोई पूर्व सूचना दिए उपर्युक्त किसी भी रियायत को वापिस लिया जा सकता है।

**11. हथकरघा परिधान :**

कुछ देशों के लिए द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राएं पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत आबंटित की जाएगी।

**12. पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी उत्तर दिनांकित बैंक प्रस्तुत करने तथा जस्त करने के संबंध में पुनः वैधीकरण प्रक्रिया तथा उपबंध :**

- (1) पी.पी.ई. तथा एन.आई. ई. प्रणालियों के मामले में निर्यातकों को हकदारी की मूल वैध अवधि के दौरान पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी अपेक्षित नहीं होगी। तथापि, 30 सितंबर तक अप्रयुक्त मात्राओं को ई.एम.डी./बी.जी. की उपरोक्त पैरा 5(5) में दी गई दर की शर्त पर 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है।
- (2) पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के मामले में एक निर्यातक को आवेदित मात्राओं पर एफ ओ बी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से ई.एम.डी./बी.जी. देनी होगी।
- (3) सामान्यतः ई.एम.डी. डिमांड ड्राफ्ट, एफ डी आर जिसकी ए ई पी सी द्वारा एकपक्षीय रूप से नकद राशि प्राप्त की जाए अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, वैधिक वचन बढ़ता अथवा उत्तर दिनांकित बैंक भी एफ सी एफ एस से अन्यत्र प्रणालियों में ई एम डी के रूप में निम्न निर्धारित शर्तों के अधधीन स्वीकृत किए जाएंगे :

**(क) वैधिक वचनबद्धता (एल यू टी)****पात्रता**

ऐसे पात्र निर्यातकों जिनकी पी.पी.ई., एन.क्यू.ई. तथा एन.आई.ई. प्रणालियों (जिनमें पी.पी.टी. और एन.क्यू.टी. शामिल हैं) के अंतर्गत समाहित भी देशों-श्रेणियों के लिए 25,000 नग से अनधिक हकदारियां हैं, को हकदारियों की अवधि बढ़ाने तथा उनके पुनः वैधीकरण के लिए ई एम डी/बी जी के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधधीन वैधिक वचनबद्धता (एल यू टी) प्रस्तुत करने का विकल्प होगा :

- (क) यदि महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद वैधिक वचन बढ़ता के अंतर्गत शामिल की गई हकदारियों के लिए किसी भी राशि

को जम्मा करने का दावा निर्यात हकदारी वितरण नीति के अंतर्गत करते हैं तो उस स्थिति में संबंधित निर्यातक जिसने कि वैधिक वधनबद्धता प्रस्तुत की थी, डी.जी., ए.ई.पी.सी. द्वारा इस प्रकार से किए गए दावे की राशि को ऐसे दावे की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर जमा करा देगा। ऐसा न करने पर निर्यातक शिपिंग बिलों के किसी भी प्रमाणन के आवेदन अथवा प्राप्त करने के लिए, हकदारियों के अंतरण के लिए अथवा किसी भी प्रणालियों में ई.एम.डी./बी.जी. को वापिस करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ठकुर राशि जमा न कर दे तथा डी जी, ए ई पी सी निर्यातक के लिए ये सुविधाएं बहाल करने का निर्णय न ले ले।

(ख) डी.जी., ए.ई.पी.सी. ऐसे किसी भी निर्यातक के लिए ई.एम.डी./बी.जी. के स्थान पर एल.यू.टी. प्रस्तुत करने की सुविधा वापिस ले सकते हैं जो कि इस सुविधा के लिए अन्यथा पात्र हैं लेकिन वे 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जम्मा की गई किसी भी प्रकार की राशि को जमा करने में असफल रहता है।

(ग) ई. एम.डी./बी.जी. पर लागू मार्ग निर्देशी सिद्धांत तथा शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित एल यू टी पर भी लागू होंगी।

#### (ख) उत्तर दिनांकित चैक ( पी डी सी )

एफ सी एफ एस, से अन्यत्र प्रणालियों में हकदारियों को बढ़ाने के लिए इस शर्त पर उत्तर दिनांकित चैक ई.एम.डी. के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे कि यदि किसी कारण से जमा करने पर चैक अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे चैकों के आधार पर बढ़ाई गई मात्राएं संबंधित निर्यातक की किसी भावी हकदारियों के नामे डाल दी जाएंगी तथा उसे तब तक कोई आगे हकदारियां आर्बिट्ररी नहीं की जाएंगी जब तक कि वह जम्मा की गई राशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा नहीं करा देता।

उत्तर दिनांकित चैकों पर आर्बिटन के वर्ष के बाद के वर्ष की 1 जून, की दिनांक होनी चाहिए तथा ये ठकुर तारीख से छह महीनों की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए जाने के लिए वैध होने चाहिए।

एल. यू. टी. तथा उत्तर दिनांकित चैकों के रिलीज/जम्मा होने से संबंधित शर्तें वही होंगी जोकि ई एम डी/बी जी के अन्य रूप पर लागू होती हैं।

#### गारंटी आदि रिलीज करना

- (4) ऐसा निर्यातक जो कि निर्यात हकदारी का कम से कम 90 प्रतिशत का निर्यात करता है, उसकी ई.एम.डी./बी.जी. की पूरी राशि रिलीज कर दी जाएगी। डी.जी., ए.ई.पी.सी. अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में 75 प्रतिशत तक तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में 50 प्रतिशत तक उपयोग किए जाने की स्थिति में उपयोग में जितनी कमी रही है उसके समानुपात ई.एम.डी./बी.जी. जम्मा कर लेगा। यदि निर्यात हकदारी आर्बिटन का उपयोग उपरोक्त प्रतिशत से कम रहता है तो ई.एम.डी./बी.जी. की पूरी राशि जम्मा कर ली जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उपयोग का परिकलन अलग-अलग हकदारियों अथवा प्रत्येक प्रणाली के आधार पर अलग से किया जाएगा।
- (5) यदि एक संबंधित निर्यातक पहले आओ पहल पाओ प्रणाली के अंतर्गत या तो मूल वैधता अवधि के दौरान अथवा मूल वैधता अवधि की समाप्ति के 3 दिनों की अवधि के भीतर अपनी हकदारियां वापिस कर देता है तो ई.एम.डी./बी.जी. अथवा एल.यू.टी. में लागू राशि का 50 प्रतिशत रिलीज कर दिया जाएगा।
- (6) ई.एम.डी./बी.जी. की जम्मा की गई समस्त राशि सरकार के पब्लिक डिपॉजिट खाते में जमा कर दी जाएगी जिसका संचालन ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा सरकार समय-समय पर निर्णय करेगी।

#### 13. ई एम डी/बी जी/उत्तर दिनांकित चैक/एल यू टी जम्मा के खिलाफ अपील

- (1) एक निर्यातक को जब उपर्युक्त 12(4) के अन्तर्गत महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जम्मा के आदेश से हानि पहुंचती है तो वह जम्मा की ऐसी सूचना के प्रेषण के 60 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर यथा शीघ्र निर्णय देंगे। अपीलों को निपटारते समय वह "अपरिहार्य घटना" की स्थितियों के अलावा इस अधिसूचना में परिभाषित जम्मा की शर्तों को भी ध्यान में रख सकते हैं। यदि आवेदक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो वे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर भी देंगे। इस प्रयोजन के लिए वस्त्र आयुक्त से अभिप्राय वस्त्र आयुक्त तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए अन्य अधिकारी से होगा जिन्हें वस्त्र आयुक्त स्पष्ट या अन्यथा रूप में आवश्यक उत्तरदायित्वों का प्रत्योजन करती है। यदि निर्यातक वस्त्र आयुक्त, बम्बई के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह पत्र भेजने के 60 दिन के भीतर निर्णय के विरुद्ध अपीलीय समिति, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। ऐसी अपीलें सदस्य सचिव, अपीलीय समिति को संबोधित की जानी चाहिए।

- (2) अपीलीय समिति की संरचना निम्न अनुसार होगी :—

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| (1) संयुक्त सचिव (निर्यात)      | अध्यक्ष |
| वस्त्र मंत्रालय।                |         |
| (2) विधि व न्याय मंत्रालय       | सदस्य   |
| के उस मंत्रालय द्वारा यथा नामित |         |

एक अधिकारी ।

(3) निर्यात आयुक्त

सदस्य

(4) निदेशक उप सचिव (निर्यात),

सदस्य-सचिव

वस्त्र मंत्रालय ।

#### 14. रोके गए माल को रिलीज करवाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

- (क) जहां आयातक देश द्वारा लदान की गई गैर-कोटा श्रेणी अथवा किसी अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तो वहां पुनर्वर्गीकृत श्रेणी के लिए निर्यात प्रमाण पत्र/बीजा निर्यातक पी पी ई प्रणाली में आवश्यक कोटा को वापिस किए जाने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए निर्यातक एफ सी एफ एस से अन्यत्र प्रणालियों में अपनी निजी हकदारियों में से मात्रा अथवा अन्तरण से प्राप्त की गई मात्रा को अभ्यर्पित कर सकता है । यदि मामला 20 सितम्बर के बाद जबकि हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं है, निपटारा जाना है तथा निर्यातक के पास अभ्यर्पित करने के लिए अपनी कोई हकदारियां नहीं हैं तो उस स्थिति में वह इस आशय के वचन दे सकता है कि वह बाद के वर्ष की हकदारी (उसकी निजी अथवा हस्तांतरित) में से 31 जनवरी तक आवश्यक मात्रा को अभ्यर्पित कर देगा । ऐसी वचनबद्धता के साथ मात्रा के 50 प्रतिशत तक के एफ ओ बी मूल्य तक की बी जी/ई एम डी प्रस्तुत की जानी चाहिए । मात्रा के अभ्यर्पित किए जाने के बाद ही बी जी/ई एम डी रिलीज की जा सकती है । यदि वचनबद्धता के अनुसार मात्रा अभ्यर्पित नहीं की जाती है तो बी जी/ई एम डी जफ्त की जा सकती है । ऐसे मामले में अपेक्षित मात्रा अभ्यर्पित करने के बाद ही निर्यातक को परवर्ती वर्ष के लिए किसी देश-श्रेणी में पी.पी.ई. आबंटन किये जा सकते हैं ।
- (ख) यदि एफ सी एफ एस प्रणाली में ए ई पी सी द्वारा रिलीज की गई मात्राओं में से पुनर्वर्गीकृत श्रेणियों में आबंटित न किया गया अधिशेष उपलब्ध रहता है तो रोके गए परेषण के लिए निर्यात प्रमाणपत्र/बीजा ऐसे अधिशेष को नामे डाले जाने के बाद ही जारी किए जाएंगे तथा निर्यातक को कोई मात्रा अभ्यर्पित करनी जरूरी नहीं होगी ।
- (ग) उपर्युक्त शर्त (क) और (ख) ऐसे मामलों पर भी लागू होगी जिनमें 30 सितम्बर के बाद समय अवधि बढ़ाने के बाद एफ सी एफ एस प्रणाली के अन्तर्गत अथवा पी पी ई प्रणाली के अन्तर्गत प्रभावित हुए लदान के लिए क्रेता को बदलना अपेक्षित है तथा ये शर्तें ऐसे मामलों पर भी लागू होंगी जिनमें आयातक देश में परिवर्तन करना अपेक्षित है ।
- (घ) जब प्रतिबंधित श्रेणी में निर्यात के लिए लदान की गई वस्तुओं को उपयुक्त अनुसार अन्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तब देश से जहाज से भेजने के लिए प्रयुक्त हकदारी निम्नलिखित शर्तों पर निर्यातक को वापिस की जाए :—
- (1) निर्यातक उस मूल निर्यात प्रमाणपत्र/बीजा को वापिस कर दे जोकि उसे जारी किया गया था ।
  - (2) हकदारी प्रमाणपत्र, जिसे निर्यात के समय नामे डाला गया था, अनुरोध किए जाने पर संबंधित मात्रा के लिए वैध बना रहेगा ।
- (ङ) ऐसी मदों के मामले में जिन्हें आयातक देशों द्वारा प्रतिबंधित मदों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, उन्हें प्रतिबंधित मदों से छूट प्राप्त हथकरघा परिधानों के रूप में अथवा 'इण्डिया आइटम्स' के रूप में निर्यात किया जाता है तो डी जी, ए ई पी सी, वस्त्र मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् बीजा निर्यात/प्रमाणपत्र जारी करेंगे ।

#### 15. निर्यातकों द्वारा कोटा संबंधी अनाधार से निपटने की प्रक्रिया

- (1) प्रवर्तन समिति नामक एक समिति की स्थापना की गई है जिसकी संरचना निम्न अनुसार है :—

1. वस्त्र आयुक्त	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य
3. विधि तथा न्याय मंत्रालय का एक अधिकारी	सदस्य
4. अध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य
5. 3 उपाध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य
6. अपर महानिदेशक (कोटा नीति), अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् ।	सदस्य

- (2) प्रवर्तन समिति ऐसे मामलों का निपटान करेगी जिनमें निम्नलिखित में से किसी एक का भी उपयोग अन्तर्ग्रस्त होगा जोकि काटों को प्राप्त करने, बढ़ाने, उपयोग करने अथवा उपयोग के संबंध में प्रमाण देने से संबंधित होंगे :

- (क) कोई भी धोखाधड़ी का क्रियाकलाप
- (ख) तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का मामला
- (ग) ऐसे किसी भी दस्तावेज को गलती ढंग से प्रस्तुत करना अथवा जालसाजी करना अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जो वास्तविक नहीं हैं ।

(घ) हकदारियों को बढ़ाने के लिए ऐसे उत्तर निर्दिष्टित बैंक प्रस्तुत करना जिन्हें उसके बैंक में प्रस्तुत करने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

- (3) प्रवर्तन समिति ऐसे निर्यातकों से संबंधित उन मामलों का भी निपटारा करेगी जिनमें ऐसी किसी मद का निर्यात किया जाना पाया गया है अथवा जिसके निर्यात के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी निर्यात मद में प्रयुक्त होने के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित कोई रंजक, रसायन, रंगद्रव्य अथवा अन्य सामग्री निहित है ।
- (4) जब उपर्युक्त से संबंधित कोई मामला ध्यान में आता है तो महानिदेशक, एं ई पी सी संबंधित निर्यातकों को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे तथा ऐसे मामलों को प्रवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । प्रवर्तन समिति ऐसे मामलों पर विचार करेगी तथा जिनमें निर्यातक के स्पष्टीकरण यदि कोई हो, की जांच करने तथा निर्यातक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद दोषी पाया जाता है तो निर्यातक को उसके द्वारा पहले से ही प्राप्त की गई हकदारियों का आगे उपयोग करने अथवा अन्तरण करने के लिए किसी विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है ।
- (5) गम्भीर मामलों में महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई से पहले प्रक्रिया के पूरा हुए नगैर तथा समिति द्वारा निर्णय को अंतिम रूप देने से पूर्व निर्यातक को अस्थायी तौर पर वितरित किया जा सकता है ।
- (6) प्रवर्तन समिति के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक प्रवर्तन अपील समिति गठित की जाएगी जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा :—

संयुक्त सचिव (निर्यात), वस्त्र मंत्रालय	अध्यक्ष
विधि तथा न्याय मंत्रालय के विधि सचिव	सदस्य
द्वारा नामित अधिकारी	
निर्यात आयुक्त	सदस्य
निदेशक, उप सचिव (निर्यात), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य-सचिव

प्रवर्तन अपील समिति निर्यातक से अपील प्राप्त होने पर अथवा महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् से स्वयं ब्यौरे मंगा कर प्रवर्तन समिति के आदेशों की समीक्षा, संशोधन, आशोधन अथवा उनको रद्द कर सकता है ।

- (7) ऐसे मामलों में, जिनमें समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जांच करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निर्यातक को धोखाधड़ी करने अथवा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने अथवा दस्तावेजों को झुठलाने अथवा कुछ रसायनों के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने, जैसा भी मामला हो, के लिए दोषी पाती है तो संबंधित निर्यातक को विशिष्ट अवधि के लिए पहले से प्राप्त की गई निर्यात हकदारियों का आगे प्रयोग करने अथवा उन्हें हस्तांतरित करने तथा किसी प्रकार की अन्य हकदारियां प्राप्त करने से विवर्जित किया जा सकता है ।

#### 16. सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्लीयरेंस

- (क) प्रतिबंधित मदों के अंतर्गत उत्पाद जिनमें वे मदें भी शामिल हैं जो कि संयुक्त राज्य अमरीका में विशिष्ट सीमाओं के अध्याधीन नहीं हैं

पोतलदान बन्दरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों तथा अलग-अलग माल के लिए जारी किए गए शिपिंग बिलों की जांच करने के बाद दी जाएगी ।

- (ख) हथकरघा परिधान

कनाडा में प्रतिबंधित मदों के समतुल्य जिसमें टेलर्ड कालर शर्ट्स शामिल नहीं हैं, सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के लिए और यू एस ए से संबंधित कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं के पोतलदान की अनुमति डी जी, एं ई पी सी द्वारा शिपिंग बिलों के प्रमाणीकरण के अतिरिक्त संयोजन प्रमाणपत्र के भाग 2 में वस्त्र समिति द्वारा किये गए निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी जायेगी ।

- (ग) "इण्डिया आइटम्स" के अन्तर्गत आने वाले परिधान

"इण्डिया आइटम्स" के संबंध में जो कि भारत की परम्परागत लोक रीति के हस्तशिल्प की वस्त्र उत्पाद मदें हैं, उनका ई यू, संयुक्त राज्य अमरीका, नार्वे तथा कनाडा को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा शिपिंग बिलों के प्रमाणन के आधार पर दी जाएगी ।

#### 17. निर्यात प्रमाण-पत्र, मूल स्थान का प्रमाण-पत्र तथा बीजा

महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा उनकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा द्विपक्षीय वस्त्र करार के अन्तर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे :—



## 1. ई यू

(क) प्रतिबंधों के अन्तर्गत समस्त परिधान/निटवियर मर्दों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र ।

(ख) समस्त गैर-प्रतिबंधित परिधानों/मर्दों के लिए मूल स्थान का प्रमाणपत्र ।

## 2. नार्वे

विशिष्ट सीमाओं के अध्यक्षीन श्रेणियों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र ।

## 3. कनाडा

परिधानों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जो कि 500 अथवा उससे कम कनैडियन डालर के मूल्य के विधिवत् चिन्हित नमूनों को छोड़कर प्रतिबंधों के अध्यक्षीन है ।

## 4. संयुक्त राज्य अमरीका

250 अथवा उससे कम अमरीकी डालर के मूल्य के विधिवत् चिन्हित नमूनों को छोड़ करके समस्त/निटवियर माल के लिए वीजा ।

## (ख) हथकरघा प्रमाणपत्र

कनाडा को प्रतिबंधित मर्दों के समतुल्य सभी हथकरघा परिधानों (जिनमें टेलर्ड कालर शर्ट शामिल नहीं है) के निर्यात के मामलों में तथा ई. यू. और नार्वे को कुल प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं के संबंध में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय करारों में यथा निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

18. ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्यात हकदारियां आबंटित की गई हैं लेकिन वे उनका पूर्णरूपेण उपयोग नहीं करते हैं, वे अपने खिलाफ की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भविष्य में हकदारियां प्राप्त करने के लिए अपने आपको अयोग्य कराने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

## 19. वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षी भूमिका :

वस्त्र आयुक्त, मुम्बई निर्यात हकदारियों के आबंटन से संबंधित मामलों का दिन-प्रति-दिन पर्यवेक्षण करेंगे । एक समन्वय समिति नीति के प्रचालन की समय समय पर समीक्षा करेगी, जिसमें वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे तथा ए ई पी सी, डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी तथा एच ई पी सी के प्रतिनिधि होंगे । ऐसे मामलों में जहां विचारों में अन्तर है, वस्त्र आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा ।

20. सरकार के पास पूर्व सूचना दिए बिना उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

21. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद तथा वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नोक्त अनुसार हैं :—

## 1. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद,

15, एन बी सी सी टावर,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली - 110066.

## 2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,

न्यू सी जी ओ कम्प्लेक्स,  
न्यू मरीन लाइन्स,  
(पोस्ट बॉक्स नं. 11500),  
मुम्बई - 400020.

## 3. वस्त्र समिति

"क्रिस्टल" 79, डा. एनी बेसेंट रोड,  
मुम्बई - 400018.

## 4. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),

वेस्ट ब्लॉक - 7,  
रामकृष्णपुरम,  
नई दिल्ली - 110022.

एन. रामाकृष्णन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 1996

**No. 1/50/96-EP(T&J) I Subject :—Conditions applicable for the period 1997—99 for exports in respect of Garments and Knitwear to countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agreement on Textiles and Clothing.**

**1. Introduction :**

Pursuant to provisions contained in Item No. 11 of Appendix XLIII-I of Volume I of the Handbook of Procedures published under the Export and Import Policy (1992—97) in respect of export of readymade garments and knitwear to the USA, Canada, the European Union and Norway and in supersession of the Notification No. 1/64/95-EP(T&J) I dated 22 December, 1995 as amended subsequently from time to time, the Policy for Allotment of Entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 1997 to 1999 shall be as hereinafter detailed.

**2. Administration :**

- (i) Unless otherwise directed, the Director General, Apparel Export Promotion Council, New Delhi (DG, AEPC) shall allocate export entitlements. The DG, AEPC shall also do the necessary certification for exports of all readymade garments and knitwear covered in this Allotment Policy.
- (ii) For the purpose of this notification, the DG, AEPC shall mean and include such other officials of the AEPC to whom the DG, AEPC expressly or otherwise delegates a part or whole of the necessary functions and responsibilities.
- (iii) The DG, AEPC, notwithstanding any delegations effected by him, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the allotment policy.
- (iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate a part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.
- (v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities as per the Export-Import Policy.

**3. Base Year :**

The Phrase "Base Year" for an allotment year, wherever appearing in this Notification, shall mean the calendar year preceding the year immediately before that allotment year. For example, the base year for the year 1997 shall be the year 1995.

**4. Systems of Allotment:**

- (i) Quantities for export in each allotment year shall be allocated under the following systems at rates indicated against each of them :

System	Percentage of Annual Level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	75
(Out of which High Value Entitlement)	(5)
(b) New Investors' Entitlement (NIE)	10
(c) First Come First Served (FCFS) Entitlement	10
(d) Non-Quota Exporters' Entitlement (NQE)	5
Total	100

- (ii) Quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under the First Come First Served (FCFS) system.
- (iii) The Government of India in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above, in case it is considered so desirable, in view of changes in the demand pattern and other relevant considerations.
- (iv) The Textile Commissioner may reserve quantities for Knitwear, woollen products, children's wear or any other segment. Such reservations will operate upto 30 September and unallocated balances from the reserved quantities as on 1 October will be made available for applications in the FCFS system, without any reservations for such segments.

**5. Past Performance Entitlement (PPE) System Including the High Value Entitlement (HVE) System :****Computation-General**

- (i) The DG, AEPC shall compute PPE on the following basis.
- (ii) Available levels will be allotted pro-rata on the basis of the value of exports by the applicants in each country-category during the base year. Allotments however, will be restricted to the export performance of India in the country-category during the said period.

**Computation-H.V.E.**

- (iii) The average unit value realised by all exporters who have applied for PP Entitlement in a particular country-category during the base year would be worked out and exporters who have realised a higher unit value than the average unit value will be allotted additional quantities from the 5% reserved pool (HVE) on the basis of the difference between the unit value realised by an exporter and the average unit value realised in a country-category multiplied by the quantity exported by individual exporters in that country-category. The HVE of the individual exporters will be added to their PPE and will be subject to all the conditions applicable to PPE.

**Period of utilisation**

- (iv) For the purpose of utilisation of allotments, there shall be a single period from 1 January to 30 September. Exporters should utilise their entitlements by 30 September.

**Extension of period**

- (v) The unutilised quantities after 30 September can be extended upto 31 Decemer of the same year against EMD/BG at the rates given below, subject to the condition that the extension sought is for a specific buyer and a change of buyer will not be permitted.

Product group	EMD/BG amount
Gloves in USA	Rs. 5/- per pair
Underwear in Canada	Rs. 5/- per piece
Group A in Canada	Rs. 18/- per Sqm
Group II in USA	Rs. 18/- per SME
Categories 4, 5 and 24 in EU	Rs. 18/- per piece
Others	Rs. 32/- per piece

- (vi) The applications for such extension should be submitted, complete in all respects, before the expiry of the initial validity of the entitlement or within a grace period of 3 working days.

**Application for allotment**

- (vii) The quantities earmarked for allotment in this system shall be made available on 1 January and for this purpose, applications may be invited during the previous year.

**Transferability conditions**

- (viii) PPE shall be transferable, either in full or in part upto 20 September. However, transfers after 31 May will be restricted to 50% of the total quantity allotted to the transferer in the relevant country-category for the year.
- (ix) A transferred PPE (hereinafter referred to as PPT) shall be valid upto 30 September of the year and can be extended upto 31 December, subject to the provisions of para 5 (v) above.
- (x) Shipments against PPT will be counted as exports by the transferee.
- (xi) Transfer of a PPT will not be allowed.

**Transfer System**

- (xii) PPE transfers will be regulated by the Director General, Apparel Export Promotion Council through an Electronic Transfer Scheme with the help of an on-line computer network in which the offers of intending transferers will be displayed in the Regional Offices of the AEPC including the quantity and quota premium and the intending transferees will request for transfers on the basis of such displayed offers. The requests will be processed on a first come first served basis envisaging the allotment of the offer at the lowest premium amount to the first request received and so on.
- (xiii) The Electronic Transfer Scheme (ETS) including the date from which it will come into effect, will be separately announced by the Director General, Apparel Export Promotion Council. Till the time the ETS comes into operation, PPE transfers will be carried out in accordance with the procedures currently in vogue. The Director General, AEPC may also effect any changes in the announced ETS scheme, as and when he considers them necessary, with

adequate notice to the trade.

**First Come First Serve (FCFS) System :**

**Release Schedule**

- (i) The 10% quantities earmarked for the FCFS System shall be released on 10 January and on 10 April in two equal instalments.
- (ii) Quantities that become available by way of surrenders, flexibilities or otherwise, if any, shall be released on 10 July and 10 November. In addition, the unallocated balances that remain in the NIE System as on 1 September will be diverted to the FCFS System for applications to be received under this system from 1 October onwards. The quantities to be released on these dates alongwith the country-categories and segments where the releases are made, would be announced by the DG, AEPC sufficiently in advance before the scheduled release.

**Applications**

- (iii) Quantities shall be allocated against applications supported by L.Cs. valid on the date of application.

**Validity of allotments**

- (iv) Allotments will be valid for 75 days from the date of allotment and no extension will be granted.

**System of allotment**

- (v) Allotments under the FCFS system would be subject to EMD/BG @ 5% of FOB value of the quantity involved.
- (vi) The Textile Commissioner will fix the maximum quantity that can be applied for by any applicant for each country-category under this system per day.
- (vii) Allotments shall be granted on FCFS basis, and on a day when available quantities are over subscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on the day.

**Transferability**

- (viii) FCFS allotments will NOT be transferable.

**7. New Investors' Entitlement (NIE) :**

**Allotment**

- (i) Allotments under the NIE system would be made only to exporters registered, as manufacturer-exporters' and who have invested a minimum amount of Rs. 50 lakhs in new machinery either in an existing unit or in a new unit during a period of 12 consecutive months commencing not earlier than the first of January of the base year. NIE allotments would be made only once for a particular block of investments.
- (ii) Allotments will be restricted to applications received upto 31 August of the allotment year and any balances that may remain unallocated in the NIE System as on 1 September, would be diverted to the FCFS System.
- (iii) In this system quantities at the rate of 1000 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment would be allotted. Investments in fractions of Rs. one lac would not be taken into account for allotments of NIE.
- (iv) The quantity for which a given applicant is eligible will be divided equally in at least 5 country-categories to be opted for by the applicant. That is for every country-category, the maximum entitlement would be 200 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment. Allotments will be made only in the country-categories covered by the production facilities of the manufacturing unit. In case an exporter is constrained to opt for less than 5 country-categories, because his items of production do not cover 5 country-categories, the total quantities allotted to him would be restricted to his choice of country-categories multiplied by 200 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment. In case an exporter opts for more than 5 country-categories, his NIE allotment would be distributed equally among the different country-categories subject to the ceiling of 1000 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment.

**Utilisation of allotments**

- (v) Exporters should utilise their entitlements by 30 September. The unutilised quantities after 30 September can be extended upto 31 December of the same year subject to the same stipulations as applicable for such extension of PP Entitlements.

**Transferability**

- (vi) NIE will NOT be transferable.

**Guidelines by Textile Commissioner**

- (vii) Detailed guidelines for eligibility and the procedure for submission of applications would be issued by the Textile Commissioner. The Textile Commissioner would invite applications and decide the admissible value of investments of individual exporters. On that basis the DG, AEPC will allocate the entitlements.

**Miscellaneous**

- (viii) Quantities earmarked for allotment/extension against the NIE applications of 1996 will be deducted from the 10% levels earmarked for the NIE system for 1997 and the balance that remains after such allotments/extension would be allotted against applications received for 1997.
- (ix) In case no NIE balance is available in a country-category where an exporter desires an allotment, he will have a choice of either opting for some other country-category where he is eligible and a balance is available, or opting for an allotment in the same country-category for the following allotment year.

**8. Non-quota Exporters' Entitlement (NQE) System :**

- (i) Exporters of garments to non-quota countries and non-quota garments to quota countries shall be eligible for allotment under this system provided the payment is received in free currency, and the exporter has a minimum export performance of Rs. 15 lacs during the base year. Exports of garments to Russia will, however, not be taken into account for NQE allotments.

**Agency**

- (ii) Entitlements under this system shall be calculated and allotted by DG, AEPC on the basis of value of admissible exports during the base year and the levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants.
- (iii) An exporter shall be permitted a choice of ten country-category combinations for allotment.
- (iv) Conditions applicable to PPE, shall also be applicable to NQE, mutatis mutandis.

**Transferability**

- (v) NQE is transferable (to be referred to as NQT after transfer) and the conditions of transfer shall be the same as in the case of PPE.

**9. Validity of Certification of Shipping Bills :**

- (i) Validity of certifications on shipping bills in respect of the PPE and NQE Systems including PPT and NQT and NIE would be 75 days or upto the validity of the entitlement certificate, whichever is earlier. Revalidation will be permitted upto the expiry of the entitlement certificate.
- (ii) Validity of certification on shipping bills in respect of FCFS allotments would be 75 days from the date of allotment. No extensions would be permitted.
- (iii) Notwithstanding anything contained in this paragraph, the Textile Commissioner may grant extension of validity period upto five working days in individual cases if he is satisfied that the exporter concerned could not export within the period due to circumstances beyond his control.

**10. Slow Moving Items :**

- (i) An item may be declared slow-moving, if during the base year, its utilisation has been less than 75% of the base level. The Director General, AEPC would declare the items that are slow moving, latest by 1 December of the previous year.
- (ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, the following relaxations shall ordinarily be available for slow moving items :
  - (a) An exporter would have to furnish 1% of FOB value as EMD/BG instead of 5% under the FCFS system.
  - (b) The quantitative ceiling stipulated for the FCFS system vide para 6 (vi) above shall not be enforced.
  - (c) L/Cs as stipulated in Para 6 (iii) above would not be required for applying under the FCFS System.
  - (d) The extent of utilisation for proportionate forfeiture will be 50% of the quantities allotted instead of 75% applicable to the other country-categories.
- (iii) Any of the above relaxations may be withdrawn without advance notice by the Textile Commissioner on the basis of the current demand pattern.

**11. Handloom Garments :**

Special quantities reserved for handloom garments for certain countries would be allotted under the FCFS system.

**12. Revalidations Procedures and Provisions Regarding Submission and Forfeiture of Earnest money Deposits/Bank Guarantees/Post dated Cheques :**

- (i) In the case of the PPE, NIE and NQE systems, exporters would not be required to furnish EMD/BG during the original validity of the entitlements. Unutilised quantities as on 30 September could be extended till 31 December subject to EMD/BG at the rates given at para 5 (v) above.
- (ii) In the case of the FCFS system, an exporter shall be required to give EMD/BG @ 5% of the FOB value on the quantities applied for.
- (iii) EMD should ordinarily be furnished by way of Demand Draft, FDR unilaterally encashable by AEPC or Bank Guarantee. However, Legal Undertakings or Post Dated Cheques will also be accepted as EMD in systems other than FCFS, subject to the conditions stipulated below :

**(A) Legal Undertaking (LUT)—****Eligibility**

Eligible exporters who have entitlements of not less than 25,000 pieces for all country-categories taken together under the PPE, NQE and NIE systems (including PPT & NQT) would have an option of submitting a legal Undertaking (LUT) in place of EMD/BG, for extension and revalidation of the entitlements subject to the following conditions :

- (a) If the DG, AEPC raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy, for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by a Legal Undertaking, the exporter concerned who had submitted the Legal Undertaking, would have to remit the amounts so claimed by the DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim without demur or protest, failing which the exporter shall not be eligible to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of Entitlements or return of EMD/BGs in any system until the amounts are remitted and the DG, AEPC decides to re-instate these facilities for the exporter.
- (b) The DG, AEPC may withdraw the facility of submitting LUT in place of EMD/BG for any exporter who is otherwise eligible for the facility, but has failed to remit any forfeiture amount within the stipulated period of 90 days.
- (c) The guidelines and stipulations applicable to EMD/BD shall also apply to LUT, mutatis mutandis.

**(b) Post Dated Cheques (PDC)—**

Post Dated Cheques will be accepted as EMD, in systems other than FCFS, for extension of entitlements subject to the condition that if the cheque is dishonoured on deposit for any reason, the quantities extended against such cheques would be debited to any future entitlements of the concerned exporter and he will not be allotted any further entitlements until the amount covered by the forfeiture is remitted by way of Demand Draft.

The Post Dated Cheques should be dated 1 June of the year following the year of allotment and should be valid for presentation during a period of 6 months from that date.

The stipulations relating to release/forfeiture of the LUT and the Post Dated Cheques would be the same as applicable to the other forms of EMD/BG.

**Release of guarantees etc.**

- (iv) The EMD/BG of an exporter who exports not less than 90% of the export entitlement obtained/extended against it shall be released in full. The DG, AEPC shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is upto 75% in case of fast moving items and upto 50% in case of slow moving items, proportionate to the short-fall in utilisation. If the utilisation of an export entitlement allocation is less than the above percentages, EMD/BG shall be forfeited in full. For this purpose utilisation shall be computed either on the basis of individual entitlements or on the basis of each system separately.
- (v) If an exporter surrenders his entitlements under the FCFS system either during the original validity period or within a period of 3 days of the expiry of the original validity, 50% of the applicable amount in the EMD/BG would be released.
- (vi) Amounts from forfeited EMD/BG shall be deposited into a Public Deposit account of the Government, to be operated in such manner as the Government decides from time to time.

**13. Appeal Against Forfeiture of EMD/BG/Post Dated Cheque/LUT :**

- (i) An exporter, when aggrieved by an order of forfeiture by the DG, AEPC under para 12 (iv) above, may appeal to the Textile Commissioner against such forfeiture within 60 days of despatch of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation, give a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he may take into consideration the conditions of forfeiture spelt out in this Notification in addition to 'force majeure' conditions. He shall also give an opportunity for personal hearing if requested for by the applicant.

For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officers to whom the Textile Commissioner expressly or otherwise delegates the necessary responsibilities. If the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 60 days of the despatch of the communication conveying the decision, to the Appellate Committee, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Such appeals should be addressed to the Member Secretary, Appellate Committee.

(ii) The composition of the Appellate Committee will be as follows :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| (1) Joint Secretary (Exports),<br>Ministry of Textiles                              | —Chairman            |
| (2) An Officer of the<br>Ministry of Law & Justice<br>as nominated by that Ministry | —Member              |
| (3) Export Commissioner   | —Member              |
| (4) Director/Deputy Secretary (Exports),<br>Ministry of Textiles                    | —Member<br>Secretary |

**14. Guidelines for Obtaining Release of held-up Consignments :**

- (a) When a shipment effected in an unrestrained category is reclassified by the importing country into a restrained category or when a shipment effected in a restrained category is reclassified by the importing country into another restrained category, Export Certificates/Visas will be issued in the reclassified category after the exporter surrenders the quantity involved in the reclassified category. For this purpose, the exporter can surrender the quantity from his own entitlements in systems other than FCFS or by obtaining the quantity by transfer. If the case is to be cleared after 20 September, when transfers are not permissible, and the exporter does not have his own entitlements to surrender, he may furnish an undertaking to surrender the requisite quantity by the 31 January from the succeeding year's entitlement (his own or transferred). Such an undertaking should be backed by BG/EMD to the extent of 50% of the FOB value of the quantity. Once the quantity is surrendered, the BG/EMD may be released. If the quantity is not surrendered as per the undertaking, the BG/EMD may be forfeited. In such cases, PPE allotments in any country-category to the exporter for the succeeding year may be allotted to him, only after the requisite quantity is so surrendered.
- (b) If unallocated balance is available in the reclassified categories from the quantities released by the AEPC in FCFS system, the Export Certificate/Visa for the held-up consignment will be issued after debiting such balance and the exporter will not be required to surrender any quantity.
- (c) The stipulations of (a) and (b) above will also apply to cases where a change of buyer is required for a shipment that had been effected under the FCFS System or under the PPE system after obtaining extension beyond 30 September and to cases where a change of importing country is required.
- (d) Where a shipment exported in a restrained category is reclassified into another restrained category as above, the entitlement used for sending the shipment from the country may be returned to the exporter, subject to the following conditions :
  - (i) The exporter returns the Original Export Certificate/Visa that had been issued to him.
  - (ii) The Entitlement Certificate which had been debited at the time of export, remains valid for the concerned quantity when the add-back is requested.
- (e) In the case of items exported as handloom garments exempted from restrains or as "India Items", which are reclassified by the importing countries as restrained items, Visas/Export Certificates will be issued by the DG, AEPC after obtaining the approval of the Ministry of Textiles.

**15. Procedure to deal with Quota Malpractices by Exporters :**

- (i) A Committee called the Enforcement Committee is established with the following composition :—

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. The Textile Commissioner                       | —Chairman         |
| 2. Director General, AEPC                         | —Member           |
| 3. An Officer of the<br>Ministry of Law & Justice | —Member           |
| 4. Chairman, AEPC                                 | —Member           |
| 5. The three Vice Chairmen of AEPC                | —Members          |
| 6. Addl. DG/Director (Quota Policy),<br>AEPC      | —Member-Secretary |

- (ii) The Enforcement Committee will deal with cases involving the use of any one of the following, in connection with obtaining, extending, utilising or proving the utilisation of quotas :—
- (a) Any fraudulent activity
  - (b) Any misrepresentation of facts.
  - (c) Any falsification of documents or forgery or submission of documents which are not genuine.
  - (d) Submission of Post-dated cheques for extension of entitlements which are dishonoured on presentation to his bank.
- (iii) The Enforcement Committee will also deal with cases relating to exporters who are found to have exported or who have completed the formalities to export any item, which contains any dyes, chemicals, pigments or other material specifically banned for use in any export item, by the competent authority of the Government.
- (iv) When a case relating to the above is noticed, the DG, AEPC will issue a show cause notice to the exporters concerned and place the cases before the Enforcement Committee. The Enforcement Committee will consider the cases and where it finds an exporter guilty, after examining his explanation, if any, and giving an opportunity for a personal hearing, the exporter may be debarred from further utilisation or transfer of the entitlements already obtained by him and from obtaining any further entitlements, for a specified period.
- (v) In serious cases, the exporter may be temporarily debarred by the DG, AEPC before a personal hearing, pending the completion of the procedures and finalisation of a decision by the Committee.
- (vi) For hearing appeals against the decisions of the Enforcement Committee, an Enforcement Appellate Committee is constituted with the following composition :

Joint Secretary (Exports),	—Chairman
Ministry of Textiles	
An Officer of the	—Member
Ministry of Law and Justice	
as nominated by the	
Law Secretary	
Export Commissioner	—Member
Director/Deputy Secretary (Exports)	—Member Secretary
Ministry of Textiles	

The Enforcement Appellate Committee may review and amend, modify or quash the orders of the Enforcement Committee on appeal from the exporter or by calling for the details from the DG, AEPC, on its own.

- (vii) In cases where the Committee finds an exporter guilty of fraud or misrepresentation of facts or of falsification of documents or of violation of a ban on use of certain chemicals, as the case may be, after examining his explanation and giving personal hearing, the exporter concerned may be debarred from further utilising or transferring the export entitlements already obtained, and from obtaining any further entitlements for a specified period.

#### 16. Clearance by Customs :

##### (a) Products Under Restraint Including Items not Subject to Specific Limits in the USA

Shipments will be allowed by the Customs Authorities at the port of shipments after verifying the certification of export entitlement in the original and duplicate of shipping bills for individual consignments, issued by the DG, AEPC.

##### (b) Handloom Garments

For exports of all handloom garments, (except Tailored Collar Shirts) corresponding to restrained items in Canada and special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories relating to the USA, shipments will be permitted by the Customs on the basis of an Inspection Endorsement by the Textiles Committee in part 2 of the combination form in addition to certification of shipping bills by the DG, AEPC.

##### (c) Garments Falling under "India Items" :

In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to the E U, the USA, Norway and Canada on the basis of an appropriate certificate issued by the office of the Development Commissioner (Handicrafts) in addition to certification of shipping bills by the DG, AEPC.



**17. (a) Export Certificate, Certificate of Origin and Visa :**

The following certificates required under the relevant Bilateral Textile Agreements will be issued by the DG, AEPC or any other agency duly authorised in this behalf :

1. EU (a) Export Certificates and Certificates of Origin for all garment/knitwear items under restraint.  
(b) Certificates of Origin for all non-restrained garments/knitwear items.
2. Norway—Export Certificates and Certificates of Origin in respect of categories subject to restraint.
3. Canada—Export Certificates for garments that are subject to restraint except for properly marked samples valued at Canadian \$ 500 or less.
4. U.S.A.—Visa for all garment/knitwear consignments except properly marked samples valued at US \$ 250 or less.

**(b) Handloom Certificate :**

In the case of export of all Handloom Garments (except Tailored Collar Shirts), corresponding to restrained items to Canada and all Handloom Garments corresponding to the restrained categories to the EU and Norway, the Textiles Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

18. Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

**19. Supervisory Role of the Textile Commissioner :**

The Textile Commissioner, Mumbai shall exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as its Chairman and representatives of the AEPC, the Wool and Woollens Export Promotion Council and the Handloom Export Promotion Council will review the operation of the Policy periodically. On matters where there is a difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

20. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions as may be found necessary without giving prior notice.

21. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and the offices of the Textile Commissioner, the Textiles Committee and the Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :

1. The Apparel Export Promotion Council, 15, NBCC Towers, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.
2. Office of the Textile Commissioner, New C.G.O. Complex, New Marine Lines, (Post Box No. 11500), Mumbai-400020.
3. The Textiles Committee, "Crystal", 79, Dr. Annie Besant Road, Mumbai-400018.
4. Development Commissioner (Handicrafts), West Block-VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

N. RAMAKRISHNAN, Jt. Secy.

2549 GI/96-3

